

त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है।

03 अंक ज्योतिष, ग्रह और क्रिस्टल का गूढ़ संबंध

06 आधुनिकता का मृगतृष्णा: आज की युवा पीढ़ी और कैंसर को दिया जा रहा मौन निमंत्रण

08 करमजीत सिंह रिट्ट ने भवानी नगर में विकास कार्यों के उद्घाटन करके निर्माण करवाएं

# डीटीसी के अवसान की ओर दिल्ली? जनता पूछे – बस सेवा या बस कहानी!



**लेखक:- संजय कुमार बाढला**  
परिवहन नीति और सार्वजनिक हित मामलों पर विशेषज्ञ पत्रकार। पिछले एक दशक से सड़क सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन और तकनीकी नवाचार से जुड़ी नीतियों पर गहन विश्लेषण और रिपोर्टिंग करते हैं।

**संपादकीय परिचय:-** दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन हमेशा से राष्ट्रीय राजधानी की जीवनरेखा रहा है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) न केवल शहर की गति का प्रतीक रहा, बल्कि पर्यावरण-मित्र और सस्ती बस सेवा का भरोसा भी था। हालांकि, हाल के वर्षों में निगम की घटती भूमिका और कर्मचारियों के अन्य विभागों में स्थानांतरण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं सरकारी स्वयंसेवा ऐतिहासिक संस्था को धीरे-धीरे समाप्त तो नहीं कर रही। प्रस्तुत लेख में संजय कुमार बाढला ने इसी चिन्ताजनक प्रवृत्ति पर विस्तार से चर्चा की है — क्या यह प्रशासनिक पुनर्गठन है या सार्वजनिक परिवहन को कमजोर करने की योजना? \* "जनहित में सवाल: क्या दिल्ली की बस सेवा सच की राजनीति की चपेट में? \* "डीटीसी पर संकट: दिल्ली का

सार्वजनिक परिवहन दिशाहीन होता जा रहा है। \* "राजधानी की सवारी सेवा खतरे में — सरकारी की चुप्पी पर जनता की पुकार। \* "दिल्ली की सड़कें फिर निजीकरण की ओर? डीटीसी के भविष्य पर गहराया संशय। \* "सार्वजनिक परिवहन या राजनीतिक प्रबंधन? दिल्ली में डीटीसी की किस्मत अधर में।" दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बसें कभी राजधानी की पहचान हुआ करती थीं। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने वर्षों तक लाखों यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा की सुविधा दी। लेकिन अब यह संस्था अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। हाल के सरकारी आदेशों और नीतिगत फैसलों से ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे डीटीसी का ढांचा कमजोर किया जा रहा है।

शोला दीक्षित सरकार के समय नई सोएनजी बसों के साथ डीटीसी ने पर्यावरण मित्र परिवहन मॉडल पेश किया था। मगर आम आदमी पार्टी के शासनकाल में बसों की नई खरीद लगभग ठप पड़ गई। इसका सीधा असर निगम की परिचालन और राजस्व स्थिति पर पड़ा। अब, भाजपा-नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर भी यह आरोप लग रहे हैं कि वह इसी नीति को जारी रखते हुए निगम की संपत्तियों के पुनः उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में जारी आदेश में डीटीसी के 340 कर्मचारियों को राजस्व विभाग में स्थानांतरित किया गया है। यह कदम इस आशंका को और बल देता है कि निगम के परिचालनिक ढांचे को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। **सवाल यह उठता है कि जब डीटीसी की सबसे बड़ी आय स्रोत — बस सेवा — को ही प्रभावित किया जा रहा है, तो निगम टिकेगा कैसे?** सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सार्वजनिक परिवहन को घाटे का सौदा मानना जनता के हित में नहीं है। बस सेवा कोई व्यावसायिक उद्यम नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। यदि डीटीसी जैसी संस्थाएं खत्म होती हैं तो दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या और प्रदूषण दोनों

बढ़ेंगे, जबकि जनता की सुविधा और सुरक्षा घटेगी। **पिछले दो दशकों की नीति याद करें** — ब्लू लाइन बस सेवा को सुरक्षा कार्यों से बंद किया गया था, क्योंकि निजी संचालक अनुशासन और रखरखाव के मानक पूरे नहीं कर पा रहे थे। अब वही मॉडल यदि दोबारा लागू होता है, तो यह इतिहास से सबक न लेने जैसा होगा। डीटीसी की संपत्तियां आज भी सबसे अधिक मूल्यवान हैं, जिन पर दिल्ली सरकार सीधा कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन यदि निगम को 'घाटे में चलने वाला' घोषित कर दिया जाए, तो उसकी भूमि और परिसंपत्तियों के पुनर्विकास का रास्ता खुल जाएगा। यही स्थिति अब धीरे-धीरे बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली के नागरिक हमेशा से एक ऐसी बस सेवा के हकदार रहे हैं जो सुरक्षित, समयानुसार और सुलभ हो। यदि सरकार सार्वजनिक परिवहन को नीतिगत प्राथमिकता से बाहर रखती है तो यह केवल एक निगम का अंत नहीं, बल्कि जनहित की उस भावना की अवहेलना होगी जिसे कभी डीटीसी को दिल्ली की पहचान बनाया था। **अब समय है कि सरकार साफ करे** — क्या दिल्ली की सड़कें फिर से जनता की सवारी से भरींगी या फिर निजी वाहनों और प्रदूषण के धुंए में जनता की उम्मीदें खोजाएंगी?

## परिवहन विशेष जनहित विशेष कॉलम

# डिजिटल इंडिया में विधवाएं और बुजुर्गों की ऑफलाइन उम्मीदें

**डिजिटल इंडिया युग में पेंशन प्रक्रिया जब से 'ऑनलाइन' घोषित हुई, तब से इंतजार में बुजुर्ग और विधवाएं 'ऑफलाइन' उम्मीदें लेकर बुजुर्ग और विधवाएं बैठे हैं पेंशन के इंतजार में**

संजय कुमार बाढला, मुख्य संपादक, सामाजिक मुद्दों के विश्लेषक

दिल्ली के सरकारी दफ्तरों की खिड़कियों के बाहर पेंशन फाइल लिए जो बुजुर्ग, और विधवाएं खड़े नजर आते थे वह अब साइबर कैफे की कतारों में खड़े नजर आते हैं।

\* अब उन्हें पहले की तरह धूप नहीं जलाती, पर हा सर्वर डाउन जरूर हो जाता है।

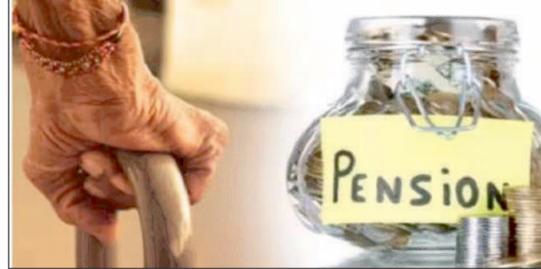
\* अब पहले की तरह फाइल गायब होने की चिंता नहीं रही पर अब "आनलाइन फॉर्म भर कर सक्सेसफुली" के स्क्रीनशॉट का इंतजार बढ़ गया बदल — पर नतीजा तब तक वही है, उन्हें इंतजार पहले भी था, और अब भी है।

जबसे दिल्ली में "जनकल्याण" के नारे डिजिटल स्क्रीन पर चमकने लगे हैं, तबसे पेंशन भी तकनीकी दौर में 'क्लिक' हो गई है — क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, गलती से अप्लाई हो गई तो फिर सिस्टम के जवाब का इंतजार कीजिए।

दिल्ली सरकार की रणनीति देखिए बिना किसी पूर्व सूचना के आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करवाते हैं रात के दस बजे और रात तीन बजे ही कर दिया जाता है बंद।

**यह गणित दिल्ली सरकार के अतिरिक्त सिर्फ वही समझ सकता है जो नींद के बजाय सर्वर के साथ जागता हो।**

दिल्ली सरकार की रणनीति देखिए एक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदनों की सीमा दो सौ सीमित जब की आवेदन कर्ता हजारां, किस गणितज्ञ ने तय की सीमा



और क्यों यह रहस्य अब भी कायम है। **सच में ऐसा लगता है जैसे पीएम घोषणाएं और दिल्ली सरकार द्वारा चालित/ घोषित जनकल्याण योजना जनकल्याण के प्रति नहीं, अपितु कोई सीमित 'कोटा' स्कीम की घोषणा हो।** सबसे बड़ा आश्चर्य यह कि सरकार के पास हर नागरिक का आधार और उम्र का विवरण है और उसके बाद भी जानबूझ कर बुजुर्गों और विधवाओं को वेबसाइट पर खुद को साबित करने की मजबूरी बना रही है। यह सवाल अब सीधा और स्पष्ट है — योजना आई जरूर, पर पहुँची कितनी तक?

तकनीकी साक्षरता की कमी के कारण लाखों बुजुर्ग और विधवाएं या तो एजेंटों पर निर्भर हैं, या उन साइबर कैफे के मालिकों पर जो तकनीकी सेवा के नाम पर पेंशन की ताकत का नया बाजार चला रहे हैं।

\* तकनीक सुविधा का माध्यम बननी चाहिए थी, बाधा का नहीं। \* सरकार चाहे तो आधार-डेटा के आधार पर स्वतः यात्रा तय कर पेंशन

जारी कर सकती है। हर जिले में एक 'सहायता केंद्र' या मोबाइल वैन भी बुजुर्गों और विधवाओं के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकते हैं। यह सिर्फ सुविधा नहीं — सम्मान की पुनर्स्थापना होगी। जनहित में बस यही कहना है — अगर पेंशन फिलहाल नहीं पहुँची है तो कम से कम "आपका आवेदन प्रक्रिया में है" का एसएमएस भेज दीजिए। ताकि इन बुजुर्गों और विधवाओं को यह महसूस हो सके कि डिजिटल इंडिया ने उन्हें भुलाया नहीं है, बस इंतजार की लिमिट थोड़ी बढ़ा दी है।

**दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक और विधवा पेंशन के लाखों आवेदन अब भी लंबित।** \* विधानसभा क्षेत्रवार सीमित कोटा आवंटन से असमान वितरण की आशंका। \* आवेदन पोर्टल के समय और सर्वर क्षमता पर कई शिकायतें दर्ज। \* डिजिटल साक्षरता की कमी के चलते बुजुर्ग और विधवाएं अब भी विचलितियों पर निर्भर।

# जिस ऐप से रोजाना सब्जी और दूध मंगाते हैं, उसी ने दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली।

पिकी कुंडू  
सुबह करीब 8 बजे, शिवम की दादी घर में अचानक गिर पड़ीं। होश नहीं था, बस दिल धड़क रहा था। तुरंत 112 पर कॉल किया गया, लेकिन एंबुलेंस आने में देरी हो रही थी। इसी बीच शिवम को याद आया कि उन्होंने हाल ही में ब्लिंकित ऐप पर एंबुलेंस इन 6 मिनट फीचर देखा था। बिना समय गंवाए ऐप खोला, रिक्वेस्ट डाली। 1 मिनट के अंदर कर्मचारी कॉल आ गया और सिर्फ 4-6 मिनट में एंबुलेंस घर के दरवाजे पर थी।

एंबुलेंस में मौजूद दो नर्सों ने तुरंत बीपी और शुगर चेक की। दादी की ब्लड शुगर 40 तक गिर चुकी थी। फौरन ड्रिप दी गई और करीब 10 मिनट में होश लौट आया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया गया। सब ठीक होने के बाद शिवम ने फ्रीस पूछी उन्हें लगा यह पेड सर्विस होगी लेकिन जवाब चौंकाने वाला था। ब्लिंकित की तरफ से ये सर्विस मुफ्त है। ये शिवम ने अपने अनुभव में साझा किया। बहुत से लोगों को इस सर्विस के बारे में पता भी नहीं होगा।



# बुराड़ी क्षेत्र के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना

परिवहन विशेष न्यूज  
बुराड़ी का राशन कार्यालय बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब क्षेत्रवासियों को राशन से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए गुलाबी बाग जाना पड़ेगा। यह निर्णय आम जनता के लिए अत्यधिक असुविधाजनक एवं जनविरोधी है। दिल्ली सरकार के इसी तुगलकी और जनविरोधी निर्णय के विरोध में 19 जनवरी को सुबह 11 बजे कोशिक एन्क्लेव पेट्रोल पंप के सामने स्थित राशन कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र की सभी RWA, सामाजिक संस्थाओं एवं आम नागरिकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर जनहित में आवाज बुलंद करने की अपील की जाती है। **अपील:- आइए, एकजुट होकर इस जनविरोधी फैसले का विरोध करें।**



बुराड़ी का राशन कार्यालय बंद

# टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html |  
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

## आज का साइबर सुरक्षा विचार: "साइबर स्लीपर सेल्स: संप्रभुता पर मौन घेराबंदी"

**भारत का साइबर युद्धक्षेत्र अब केवल**  
धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहा — यह अब घुसपैठ का युद्धक्षेत्र बन चुका है। जांचों ने एक खतरनाक गठजोड़ उजागर किया है: चीनी अपराध सिंडिकेट्स और पाकिस्तान-आधारित साइबर ऑपरेटर्स मिलकर भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में गहराई तक साइबर स्लीपर सेल्स स्थापित कर रहे हैं। ये केवल धोखाबाज नहीं हैं — ये डिजिटल विध्वंसक हैं, जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करना, जनविश्वास को कमजोर करना और महत्वपूर्ण अवसंरचना को पंगु बनाना है। साइबर स्लीपर सेल्स क्या हैं? छिपे हुए डिजिटल ऑपरेटिव्स — मानव या बॉट — जिन्हें निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है और आदेश मिलने पर सक्रिय किया जाता है। सक्रिय होने पर ये हमला करते हैं: 1. डेटा चोरी (Data Exfiltration) — संवेदनशील सरकारी और वित्तीय जानकारी चुराना 2. अवसंरचना को नुकसान

(Infrastructure Sabotage) — ग्रिड, दूरसंचार, परिवहन, बैंकिंग को बाधित करना 3. आतंकी फंडिंग (Terror Funding) — वॉलेंट्स और क्रिप्टो के माध्यम से धन प्रवाह करना 4. धुंधला अभियान (Disinformation Campaigns) — झूठी खबरें फैलाकर समाज को विभाजित करना 5. भर्ती और कट्टरपंथीकरण (Recruitment & Radicalization) — युवाओं को चरमपंथी नेटवर्क में फँसाना **निष्क्रिय अवस्था (Dormant Phase)** 1. सामान्य उपयोगकर्ताओं की तरह दिखते हैं। 2. सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऐप्स, वॉलेट्स के रूप में संचालित होते हैं। 3. चुपचाप डेटा इकट्ठा करते हैं और नेटवर्क में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। **सक्रिय अवस्था (Activation Phase)** 1. गोपनीय डेटा लीक करना। 2. अवसंरचना को पंगु बनाना। 3. सीमा-पार धन का प्रवाह करना। 4. जनमत को प्रभावित करना। 5. ऑनलाइन भर्ती और कट्टरपंथीकरण



करना। **ये कैसे काम करते हैं?** 1. फेक ऐप्स और मैलवेयर — निर्दोष दिखने वाले डाउनलोड से डिवाइस पर कब्जा करना 2. फर्जी आईडी और सिम कार्ड — गुमनाम डिजिटल पहचान बनाना 3. क्रिप्टो और वॉलेट्स — धन शोधन और आतंकी फंडिंग को छिपाना 4. सोशल इंजीनियरिंग — उपयोगकर्ताओं को धोखे से संवेदनशील जानकारी देने पर मजबूर

करना **खतरा क्यों गंभीर है?** 1. वर्षों तक अदृश्य रहते हैं, आदेश पर सक्रिय होते हैं। 2. सीमा-पार नेटवर्क होने से ट्रैक करना कठिन। 3. यह केवल अपराध नहीं — संप्रभुता पर सीधा हमला है। साइबर घुसपैठ का नया प्लेबुक साइबर स्लीपर सेल्स हमारे युग के डिजिटल घुसपैठिए हैं।

छिपे हुए, धैर्यवान, घातक — ये डेटा, धन और विश्वास पर हमला करते हैं। इन्हें निष्क्रिय करना भारत की साइबर सुरक्षा का केंद्रीय हिस्सा है। **भर्ती और सक्रियण** 1. मैलवेयर से भरे म्यूजिक/गेमिंग ऐप्स 2. नकली आईडी वाले सिम कार्ड 3. डेटा चोरी के लिए लोन और निवेश ऐप्स **फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग** 1. वॉलेट्स और क्रिप्टो एक्सचेंज 2. म्यूल नेटवर्क्स और फर्जी खाते 3. परतदार लेन-देन से धन का स्रोत छिपाना **जासूसी और तोड़फोड़** 1. दूरसंचार, ऊर्जा, परिवहन, कानून प्रवर्तन प्रणालियों की जाँच 2. शत्रु राज्यों से जुड़े APT का उपयोग 3. एआई-चालित प्रचार से असंतोष फैलाना **नागरिकों के लिए** 1. सॉडिग ऐप्स डाउनलोड न करें। 2. साइबर अपराध की रिपोर्ट करें: www.cybercrime.gov.in 3. डिजिटल स्वच्छता अपनाएँ: मजबूत पासवर्ड, 2FA, अनुमतियों की जाँच 4. जागरूकता अभियानों के माध्यम से सतर्क रहें।

**नीतिनिर्माताओं के लिए** 1. क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर KYC लागू करें। 2. फॉरेंसिक लैब्स और जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण में निवेश करें। 3. स्कूलों और सार्वजनिक सेवा में साइबर साक्षरता को शामिल करें। **दांव:** 1. साइबर युद्ध के युग में संप्रभुता अब यह केवल धोखाधड़ी कॉल्स की बात नहीं है — यह डिजिटल संप्रभुता, संस्थागत अखंडता और राष्ट्रीय लचीलापन की बात है। 2. साइबर स्लीपर सेल्स एक हाइब्रिड खतरा हैं — जासूसी, अपराध और मनोवैज्ञानिक युद्ध का मिश्रण। 3. भारत की रक्षा केवल फायरवॉल्स से नहीं, बल्कि जागरूकता, समन्वय और नवाचार से होगी। **अंतिम संदेश** 1. साइबर सुरक्षा कोई विभाग नहीं — यह एक सिद्धांत (Doctrine) है। 2. हर अधिकारी। हर नागरिक। हर संस्था। 3. सभी मिलकर हम भारत की डिजिटल ढाल हैं। **आइए, सतर्कता को विजय में बदलें।**





## जिला व उपमंडल स्तर पर आज (सोमवार 19 जनवरी) को आयोजित होंगे समाधान शिविर

सुबह 10 से 12 बजे तक नागरिकों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 18 जनवरी। जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से आज सोमवार को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। जिला स्तरीय समाधान शिविर का

आयोजन लघु सचिवालय, झज्जर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे। इस अवसर पर उपायुक्त नागरिकों की विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें एवं समस्याएँ सुनेंगे तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समयबद्ध समाधान के निर्देश देगे। वहीं, उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में किया जाएगा। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच, आईएस, बेरी में एसडीएम आईएस अंकित कुमार चौकसे व बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में

समाधान शिविर आयोजित होंगे, जहां नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर प्रशासन और नागरिकों के बीच संधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में समाधान शिविर प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं गुरुवार को नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहते हैं, जिससे आमजन को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध हो सके।



### एग्री स्टैक फार्मर आईडी अभियान तेज, रविवार को भी किसानों ने बनवाई फार्मर आईडी

फार्मर आईडी से कृषि योजनाओं का लाभ प्रदान करना शासन प्रशासन का उद्देश्य : एसडीएम

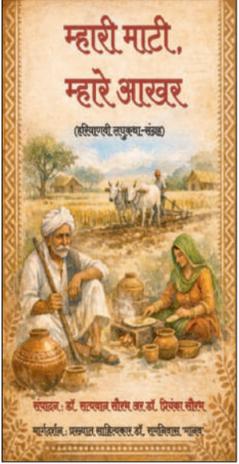
झज्जर, 18 जनवरी। एसडीएम आईएस अंकित कुमार चौकसे ने कहा कि डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के मार्गदर्शन में सरकार की डिजिटल पहल एग्री स्टैक के तहत किसानों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य लगातार प्रगति पर है। इसी कड़ी में रविवार को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने विशेष अभियान चलाते हुए किसानों की एग्री स्टैक फार्मर आईडी जेनरेट की। रविवार यानी अवकाश के दिन आयोजित किए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सुविधा प्रदान करना रहा, ताकि कार्यदिवसों में व्यस्त रहने वाले किसान भी इस महत्वपूर्ण पहल से जुड़ सकें। कृषि विभाग के अधिकारियों ने गांवों में किसानों को फार्मर आईडी बनवाने के लिए जागरूक किया। एसडीएम अंकित कुमार चौकसे ने अभियान की समीक्षा करते हुए संबंधित टीमों को शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एग्री स्टैक फार्मर आईडी किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, सब्सिडी, बीमा, ऋण और अन्य लाभ सीधे व पारदर्शी तरीके से मिल सकेंगे। एसडीएम ने किसानों से भी अपील की कि वे समय निकालकर अपनी फार्मर आईडी अवश्य बनवाएं और कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने बताया कि रविवार को कैंप आयोजित करने का मुख्य मकसद यही है कि अधिकतम किसानों को कवर किया जा सके और कोई भी पात्र किसान इस सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी इसी तरह के विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी पात्र किसानों की एग्री स्टैक फार्मर आईडी निर्धारित समय सीमा में तैयार की जा सके।

**\*नागरिक क्या न करें\***  
डीसी ने बताया कि ग्रेप चार की पाबंदियों के चलते नागरिक खुले में कचरा, पत्तियां या किसी भी प्रकार का अवशेष न जलाएं। किसी भी प्रकार का निर्माण/ध्वंसीकरण कार्य न करें। आपातकालीन/अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) डीजल जेन सेट का उपयोग ना करें। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त न हों।

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ताकि वायु गुणवत्ता में शीघ्र सुधार लाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेप-4 प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

**'म्हारी माटी, म्हारे आखर'**  
**\*हरियाणवी बोली की लेखका भेज्जण खातर च्योता\***  
हरियाणवी बोली अर हरियाणा के लोक-जीवन पै आधारित लघुकथा-संग्रह खातर रचनाकारों तै तीन-तीन लघुकथा भेजण की बिन्ती सै। एह किताब म्हें कुल इक्यावन लघुकथाकार हे शाम्ल करे जावें।  
**\*नियम अर शर्त\***

1. लघुकथा सुद्ध हरियाणवी बोली म्हें होणो चहिई।
  2. भेजी जाण आळी लघुकथा की सबद-सिम्मा 150 सबद सै।
  3. लेखक 100 सबदों म्हें अपना संक्षिप्त परिचै साथ जरूर भेज्जें।
  4. चुणे गये लेखकों नै किताब की परती छपी कीमत तै 30 परतीसत छूट म्हें दी जावैगी।
  5. लेखक खातर किताब खरीदणा जरूरी कोन्या सै।
- आण आळा लघुकथा-संग्रह हरियाणवी बोली, संस्करती अर समाज की सच्ची तस्वीर दिखणा की एक कोशिश सै। इच्छुक रचनाकार तै नियमों के हिसाब तै अपनी लघुकथा भेज्जें।  
\*✉ ई-मेल (पता) :  
satyansaurabh333@gmail.com



## दुल्हेड़ा गांव में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम आज (19 जनवरी सोमवार) को डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे ग्रामीणों से सीधा संवाद

स्वास्थ्य जांच शिविर और योजनाओं की जानकारी के लिए लगभग विभागीय स्टॉल

परिवहन विशेष न्यूज

बहादुरगढ़ (झज्जर), 18 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी की अग्रणी पहल पर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक माह आयोजित किए जाने वाले रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन इस बार आज (19 जनवरी सोमवार) को बहादुरगढ़ खंड के गांव दुल्हेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे। डीसी ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनेंगे और उनका मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे। यह जानकारी बहादुरगढ़ के एसडीएम आईएसएस अभिनव सिवाच ने दी।

एसडीएम ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हेतु स्टॉल लगाए जाएंगे तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन को गांव स्तर पर जनता से सीधे जोड़ने और उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रशासन को जमीनी हकीकत समझने और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की स्थिति जानने में मदद मिलती है।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, अपनी समस्याएँ और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि गांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

## वायु प्रदूषण को त्वरित रूप से नियंत्रित करना ग्रेप-4 का मुख्य उद्देश्य : डीसी

स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत सिटीजन चार्टर का पालन करें नागरिक वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर के चलते जिले में ग्रेप-4 की पाबंदियां लागू

बहादुरगढ़ (झज्जर)। जिले में वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार ग्रेड ड रिस्पॉस एक्शन प्लान के चौथे चरण की पाबंदियां लागू हो गई हैं।

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि ग्रेप-4 का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को त्वरित रूप से नियंत्रित करना तथा आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रशासन, उद्योग, निर्माण एजेंसियों एवं नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि नियमों की पूर्ण एवं सख्त पालना सुनिश्चित की जाए।

डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें, उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करें तथा

आवश्यक नियंत्रणात्मक कदम प्रभावी रूप से लागू करें। उन्होंने बताया कि ग्रेप चार के चलते जिला में निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी व सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश जैसी निर्माण सामग्री की वाहनों में आवाजाही बंद करनी होगी। सड़कों व पेड़ों पर पानी का छिड़काव व एंटी-स्मॉग गन का उपयोग बढ़ाना होगा। कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

**उद्योग: कोयला, लकड़ी से चलने वाले**  
उद्योग व थर्मल पावर प्लांट, स्टोन क्रशर व खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटोरों पर रोक रहेगी।

**\*नागरिक क्या करें\***  
डीसी ने कहा कि विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग व अस्वस्थ व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें। सार्वजनिक परिवहन, कार-पुलिंग व वैकल्पिक साधनों का अधिक उपयोग करें। आमजन निजी वाहनों का प्रयोग

कम करें। घर एवं कार्यालय में धूल नियंत्रण रखें, गोली सफाई (वेट क्लीनिंग) अपनाएं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मार्क का प्रयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह का पालन करें। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों व एडवाइजरी का पालन करें।

**\*नागरिक क्या न करें\***  
डीसी ने बताया कि ग्रेप चार की पाबंदियों के चलते नागरिक खुले में कचरा, पत्तियां या किसी भी प्रकार का अवशेष न जलाएं। किसी भी प्रकार का निर्माण/ध्वंसीकरण कार्य न करें। आपातकालीन/अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) डीजल जेन सेट का उपयोग ना करें। प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त न हों।

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें, ताकि वायु गुणवत्ता में शीघ्र सुधार लाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेप-4 प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

# हरियाणा बजट 2026-27 के लिए 31 जनवरी तक सुझाव दे सकते हैं नागरिक : डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल

मिस्ट्र कॉल, एआई-सहायक व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमजन दे सकता है बजट सुझाव, मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी स्वयं हितधारकों से कर रहे हैं संवाद



परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 18 जनवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण की प्रक्रिया में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार का मत है कि बजट जनहित, विकास प्राथमिकताओं और नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो। इसी उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

डीसी ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए सुझाव देने के कई माध्यम उपलब्ध कराए

गए हैं। नागरिक 7303350030 नंबर पर मिस्ट्र कॉल देकर 31 जनवरी तक अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एआई-सहायक के माध्यम से thevoxai.in/haryanabudget लिंक पर संवाद करने की सुविधा भी उपलब्ध है। विस्तृत सुझाव देने के लिए नागरिक bamsharyana.nic.in/suggestion.aspx लिंक पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

**\*मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी स्वयं हितधारकों से कर रहे हैं संवाद\***  
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह

सैनी हरियाणा बजट 2026-27 को जनभागीदारी के साथ तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से निरंतर बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में उद्योग, शिक्षा, व्यापार, कृषि, महिला उद्यमिता सहित अनेक वर्गों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 6 जनवरी को गुरुग्राम विश्वविद्यालय से इस जनभागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।

डीसी ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक राज्य के बजट निर्माण में

सोपे भागीदारी कर रहे हैं। इस पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सुझाव देने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिलावासियों से अपील की कि वे समय रहते अपने सुझाव साझा करें, ताकि बजट निर्माण की प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें बजट निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे हरियाणा के समग्र विकास को नई दिशा मिल सके।

# विश्व को अस्थिर करता अमेरिका:- वेनेजुएला और ईरान के बाद अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर- नाटो की अग्निपरीक्षा और यूरोपीय एकता की निर्णायक जीत-एक समग्र विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय संवाद और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता देकर वैश्विक सहयोग का नया मॉडल बनाने की खास जरूरत यूरोप की एकता ने यह साबित किया है कि यदि देश सामूहिक रूप से खड़े हों, तो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को भी पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब भी अमेरिका की विदेश नीति में एक पुराना साम्राज्यवादी आग्रह बार-बार उभरकर सामने आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता के सिद्धांतों को दरकिनारा करते हुए सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अमेरिका की रणनीति का हिस्सा रहा है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों, ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति और अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के आक्रामक बयान, यह सब मिलकर एक स्पष्ट अमेरिका की रणनीति का हिस्सा रहा है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों, ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति और अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के आक्रामक बयान, यह सब मिलकर एक स्पष्ट अमेरिका की रणनीति का हिस्सा रहा है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों, ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति और अब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के आक्रामक बयान, यह सब मिलकर एक स्पष्ट अमेरिका की रणनीति का हिस्सा रहा है।

साथियों बात कर हम वेनेजुएला और ईरान: हस्तक्षेप की पुरानी पटकथा को समझने की करें तो ग्रीनलैंड से पहले अमेरिका की नजर वेनेजुएला और ईरान पर रही है। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने और कथित अपहरण जैसी घटनाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा हुई। यह सब अंतरराष्ट्रीय कानून और किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत के सीधे उल्लंघन थे। इसी तरह ईरान के खिलाफ लगातार प्रतिबंध, सैन्य धमकियां और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने की नीति ने मध्य-पूर्व को लंबे समय तक संघर्ष के दलदल में धकेल दिया। इन दोनों उदाहरणों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति कूटनीति पहले नहीं, बल्कि नाटो के लिए भी एक निर्णायक परीक्षा बन गया

नाटो एक ऐसा सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि जब गठबंधन का सबसे शक्तिशाली सदस्य ही अपने सहयोगी देशों पर दबाव डालने लगे तो नाटो की नैतिकता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यूरोपीय देशों ने स्पष्ट संकेत दिया कि नाटो का मतलब केवल अमेरिकी हितों की रक्षा नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस एकजुटता ने ट्रंप प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक कदम उठाना आसान नहीं होगा। वेनेजुएला और ईरान के मामलों में जहां अमेरिका को सीमित विरोध का सामना करना पड़ा था, वहीं ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप एक स्वर में खड़ा दिखाई दिया। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम सभी ने इस बात को स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का दबाव अस्वीकार्य है। यूरोपीय एकता ने ट्रंप के उस आत्मविश्वास को झटका दिया, जिसके तहत वे मानते थे कि आर्थिक या सैन्य दबाव डालकर किसी भी देश को झुकाया जा सकता है।

साथियों बात कर हम वेनेजुएला और ईरान: हस्तक्षेप की पुरानी पटकथा को समझने की करें तो ग्रीनलैंड से पहले अमेरिका की नजर वेनेजुएला और ईरान पर रही है। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने और कथित अपहरण जैसी घटनाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा हुई। यह सब अंतरराष्ट्रीय कानून और किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत के सीधे उल्लंघन थे। इसी तरह ईरान के खिलाफ लगातार प्रतिबंध, सैन्य धमकियां और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने की नीति ने मध्य-पूर्व को लंबे समय तक संघर्ष के दलदल में धकेल दिया। इन दोनों उदाहरणों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति कूटनीति पहले नहीं, बल्कि नाटो के लिए भी एक निर्णायक परीक्षा बन गया



ग्रीनलैंड: बर्फ से ढका द्वीप, लेकिन भू-राजनीति का गर्म केंद्र रहा।

साथियों बात अगर हम ग्रीनलैंड मुद्दे को समझने की करें तो यह भले ही जनसंख्या की दृष्टि से छोटा और भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्र हो, लेकिन उसकी रणनीतिक अहमियत असाधारण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण सैन्य, ऊर्जा, खनिज और वैश्विक व्यापार मार्गों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और बर्फ के पिघलने के साथ आर्कटिक में नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जिससे यूरोप-एशिया-अमेरिका के बीच व्यापारिक दूरी कम हो सकती है। इसके साथ ही दुर्लभ खनिज, तेल और गैस जैसे संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड अब केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक शक्ति-राजनीति का केंद्र बन चुका है।

साथियों बात अगर हम अमेरिका की मंशा: आर्कटिक में वर्चस्व की होड़ को समझने की करें तो अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड में अपनी

मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। वहां पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और रडार सिस्टम इस बात का संकेत है कि वॉिशिंगटन आर्कटिक को केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि सामरिक युद्धक्षेत्र के रूप में देखता है। हालिया रणनीतिक अहमियत असाधारण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण सैन्य, ऊर्जा, खनिज और वैश्विक व्यापार मार्गों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और बर्फ के पिघलने के साथ आर्कटिक में नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं, जिससे यूरोप-एशिया-अमेरिका के बीच व्यापारिक दूरी कम हो सकती है। इसके साथ ही दुर्लभ खनिज, तेल और गैस जैसे संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड अब केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक शक्ति-राजनीति का केंद्र बन चुका है।

साथियों बात अगर हम टैरिफ हथियार:- कूटनीति की जगह आर्थिक धमकी इसको समझने की करें तो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर विरोध बढ़ता देख ट्रंप प्रशासन ने एक बार टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। घोषणा की गई कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका भेजे

जाने वाले सभी सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम स्पष्ट रूप से राजनीतिक दबाव बनाने के लिए था, ताकि यूरोपीय देश अमेरिका के रुख का समर्थन करने को मजबूर हों। हालांकि, इस बार यह रणनीति उलटी पड़ती नजर आई। यूरोपीय संसद के सबसे बड़े राजनीतिक समूह ईपीपी के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दबाव और टैरिफ धमकियों से यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौतों की आत्मा पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में अमेरिकी उत्पादों पर शून्य प्रतिशत टैरिफ की योजना को फिलहाल रोकना पड़ेगा। यह बयान इस बात का संकेत था कि यूरोप अब केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रतिरोध की नीति अपनाते के लिए तैयार है।

साथियों बात अगर हम प्लान होल्ड पर: ट्रंप को क्यों पीछे हटना पड़ा इसको समझने की करें तो, यूरोपीय देशों के संगठित विरोध और संघातित व्यापार युद्ध की आशंका के चलते ट्रंप प्रशासन को

ग्रीनलैंड योजना फिलहाल होल्ड पर डालनी पड़ी। हालांकि उन्होंने 10 प्रतिशत टैरिफ के साथ जून तक की मोहलत दी, लेकिन यह साफ हो गया कि ग्रीनलैंड पर सीधा कब्जा या खुला दबाव डालना आसान नहीं होगा। यह पहला अवसर नहीं था जब ट्रंप को अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे कदम पीछे खींचने पड़े हों, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे प्रतीकात्मक उदाहरणों में से एक है।

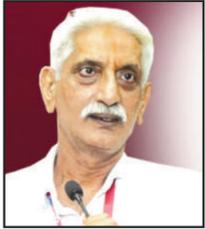
साथियों बात कर हम आर्कटिक राजनीति का भविष्य: टकराव या सहयोग? इसको समझने की करें तो ग्रीनलैंड विवाद ने आर्कटिक क्षेत्र की राजनीति को वैश्विक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में आर्कटिक सहयोग का क्षेत्र बनेगा या टकराव का। यदि अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप अपने-अपने हितों के लिए इस क्षेत्र को युद्धभूमि में बदलते हैं, तो इसका असर पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय संवाद और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जाती है, तो आर्कटिक वैश्विक सहयोग का नया मॉडल बन सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ग्रीनलैंड का मुद्दा केवल एक द्वीप तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक संघर्ष का प्रतीक है जिसमें एक ओर एकध्रुवीय प्रभुत्व की सोच है और दूसरी ओर बहुध्रुवीय नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग। यूरोप की एकता ने यह साबित किया है कि यदि देश सामूहिक रूप से खड़े हों, तो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को भी पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है। वहीं अमेरिका के लिए यह एक चेतावनी है कि

इक्कीसवीं सदी में बल और दबाव की राजनीति अब बिना प्रतिरोध के स्वीकार नहीं की जाएगी। ग्रीनलैंड ने न केवल नाटो की अग्निपरीक्षा ली, बल्कि वैश्विक राजनीति को यह भी दिखा दिया कि भविष्य का विश्व संतुलन टैरिफ की धमकियों और कब्जे से नहीं बल्कि संवाद और सहयोग से ही संभव है।



# आधुनिकता का मूगतृष्णा: आज की युवा पीढ़ी और कैंसर को दिया जा रहा मौन निमंत्रण



संजय कुमार बाटला

आज का युग तकनीक, सोशल मीडिया और त्वरित दिखावे का युग है। दुर्भाग्यवश, इसी चमक-दमक में "आधुनिक" कहलाने की होड़ ने एक खतरनाक भ्रम को जन्म दिया है।

सिगरेट पीना, हुक्का उड़ाना, रंग-बिरंगे शीतल पेय पीना और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड जंक फूड खाना—इन सबको आजादी, स्टाइल और प्रगतिशील सोच का प्रतीक मान लिया गया है। पर सच यह है कि यह आधुनिकता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के विरुद्ध एक धीमा विद्रोह है, जो कैंसर जैसे प्राणघातक रोग को न्योता दे रहा है।

1. **सिगरेट:** धूम्र में लिपटी तबाही सिगरेट केवल एक आदत नहीं, बल्कि रसायनों का जहरघोल मिश्रण है। इसके धूम्र में 7,000 से अधिक रसायन होते हैं, जिनमें कम से कम 70 सीधे कैंसर पैदा करने वाले (कार्सिनोजेनिक) हैं।

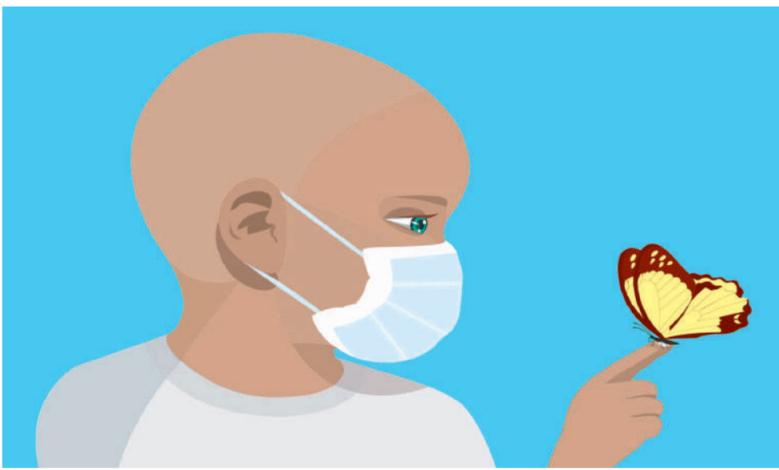
\* ये रसायन डीएनए को नुकसान पहुँचाते हैं, शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने के लिए उकसाते हैं—यही कैंसर की शुरुआत है।

\* भारत में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ धूम्रपान और तंबाकू का सेवन मुख, फेफड़े और ग्रासनली (इसोफेगस) के कैंसर का प्रमुख कारण है। चिंता की बात यह है कि अब ये कैंसर 20-30 वर्ष के युवाओं में भी दिखने लगे हैं, जिनकी जड़ें किशोरावस्था में शुरू हुई धूम्रपान की आदतों में हैं।

\* हाल के वर्षों में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तंबाकू उद्योग परोक्ष विज्ञापन और आसान उपलब्धता के जरिये युवाओं को लक्षित कर रहा है, जो आने वाले समय में एक बड़े कैंसर संकट का संकेत है।

2. **हुक्का:** "सुरक्षित" समझा जाने वाला खतरनाक धोखा हुक्का को अक्सर यह कहकर सही ठहराया जाता है कि "धुआँ पानी से छन जाता है" या "यह सिगरेट से हल्का है।" यह एक घातक मिथक है।

\* वास्तविकता यह है कि एक घंटे



का हुक्का सत्र 100 या उससे अधिक सिगरेटों जितना धुआँ शरीर में पहुँचा सकता है।

\* हाल के स्वास्थ्य अपडेट्स (2024-2025) बताते हैं कि फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू में मौजूद रसायन फेफड़ों को और अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। इससे न केवल फेफड़े और मुँह का कैंसर, बल्कि गंभीर श्वसन रोगों का जोखिम भी कई गुना बढ़ जाता है।

\* भारत में हुक्का कैफे युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे यह खतरा और गहराता जा रहा है। साझा पाइप और माउथपीस संक्रमण का अतिरिक्त जोखिम पैदा करते हैं।

3. **मीठे शीतल पेय:** मीठा जहर कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स केवल प्यास नहीं बुझाते, बल्कि शरीर में मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध और दीर्घकालिक सूजन को बढ़ावा देते हैं—ये तीनों कैंसर के सिद्ध जोखिम कारक हैं।

\* नवीन शोधों ने अत्यधिक शर्करा सेवन को कम उम्र में होने वाले कोलोरेक्टल कैंसर, मुख गुहा के कैंसर और कुछ मामलों में कैंसर के फैलाव (मेटास्टेसिस) से भी जोड़ा है।

4. **अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड:** सुविधा

की कीमत जीवन से चिप, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड बिस्किट और रेडी-टू-ईट स्नैक्स—ये सब आधुनिक

जीवनशैली का हिस्सा बन चुके हैं। पर इनमें मौजूद कृत्रिम रंग, प्रिजर्वेटिव, इमल्सीफायर और अत्यधिक नमक-चीनी आंतों के माइक्रोबायोम को बिगाड़ते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं और कैंसरकारी योगिक उत्पन्न करते हैं।

\* 2025 तक के अध्ययनों में पाया गया है कि इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने वालों में:

\* कम उम्र में प्रीकैंसरस पॉलीप्स

\* स्तन, फेफड़े और पाचन तंत्र के कैंसर का जोखिम स्पष्ट रूप से अधिक है। विशेषकर युवा महिलाओं में यह खतरा और चिंताजनक रूप से बढ़ा हुआ पाया गया है।

5. **कम उम्र में कैंसर:** एक वैश्विक चेतावनी दुनिया भर में 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में कैंसर के मामलों में तेज़ वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यही जीवनशैली जारी रही, तो 2030 तक ऐसे मामलों में लगभग 40% तक की वृद्धि हो सकती है।

\* इसके पीछे मुख्य कारण हैं—अस्वस्थ खान-पान, शारीरिक

निष्क्रियता, मोटापा और तंबाकू सेवन, जो बचपन और युवावस्था से ही शुरू हो जाते हैं।

**निष्कर्ष:** आधुनिकता की नई परिभाषा

यह अत्यंत पीड़ादायक है जब जीवन के सबसे ऊर्जावान वर्षों में युवा कैंसर जैसी बीमारी से जूझते दिखाई देते हैं—और वह भी ऐसी आदतों के कारण जिन्हें रोका जा सकता था।

1. सच्ची आधुनिकता धूम्र के छल्लों में नहीं, बल्कि स्वस्थ श्वास में है।  
2. सच्ची प्रगति रंगीन बोटलों में नहीं, बल्कि संतुलित आहार में है और 3. वास्तविक आजादी क्षणिक आनंद में नहीं, बल्कि दीर्घ और गुणवत्तापूर्ण जीवन में है।

**अब समय आ गया है कि:**

1. युवाओं को वैज्ञानिक और स्वास्थ्य-आधारित शिक्षा दी जाए

2. तंबाकू और जंक फूड के प्रचार पर सख्त नियंत्रण हो और

3. सबसे बढ़कर, हर व्यक्ति स्वयं यह निर्णय ले कि वह अपने भविष्य के साथ समझौता नहीं करेगा।

**चयन हमारे हाथ में है—आज जागरूक बनने, या कल भारी कीमत चुकाएँ।**



# कैंसर का चक्रव्यूह — आधुनिक विज्ञान से आयुर्वेद तक, क्या है इस लाइलाज डर की हकीकत?



आज की दुनिया में 'कैंसर' सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसा शब्द है जो अच्छे-भले इंसान को अंदर तक झकझोर देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने ही शरीर की बागी कोशिकाएँ हैं?

चिकित्सा विज्ञान में हुई क्रांति और आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान ने आज इस बीमारी के प्रति हमारा नज़रिया बदला है।

अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं, शरीर को इलाज के योग्य बनाने का भी है।

कैंसर क्या है और क्यों होता है? (The Biological Breakdown) सरल शब्दों में कहें तो, कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाएँ पुराने नियमों को तोड़कर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। सामान्य स्थिति में कोशिकाएँ मरती हैं और नई कोशिकाएँ बनती हैं, लेकिन कैंसर में यह सेलुलर बैलेंस बिगड़ जाता है।

**सेलुलर बैलेंस बिगड़ने के मुख्य कारण:**

\* जेनेटिक म्यूटेशन (DNA Damage): तंबाकू, रेडिएशन, रसायन

\* जीवनशैली: प्रोसेस्ड फूड, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता

\* कार्सिनोजेन्स: प्रदूषण, कीटनाशक, प्लास्टिक

\* संक्रमण: HPV, Hepatitis B & C ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कारण पोषण, इम्यूनिटी और डिटॉक्सिफिकेशन से सीधे जुड़े हुए हैं।

**किन अंगों में होता है सबसे ज्यादा खतरा? WHO के अनुसार:**

**पुरुषों में:**  
\* फेफड़े  
\* मुँह  
\* प्रोस्टेट

**महिलाओं में:**  
\* स्तन  
\* गर्भाशय ग्रीवा

**अन्य:**  
\* आंत (Colon)  
\* लिवर  
\* ब्लड कैंसर

इन सभी में एक कॉमन फैक्टर है: शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और पोषण स्थिति।

क्या आयुर्वेद में है इसका उपचार? (The Truth of Ayurveda) आयुर्वेद कैंसर को 'अबुंद' कहता है।

जहाँ आधुनिक चिकित्सा ट्यूमर को टारगेट करती है, वहीं आयुर्वेद इम्यूनिटी, अग्नि (Metabolism) और शरीर की रिकवरी क्षमता पर काम करता है।

**सच्चाई:** \* एडवांस्ड स्टेज में आयुर्वेद को अकेला इलाज मानना जोखिम भरा हो सकता है लेकिन एडजुवंट थेरेपी के रूप में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

**आयुर्वेद + सही न्यूट्रिशन** = इलाज को सहने की शक्ति = साइड-इफेक्ट्स से उबरने में मदद

**प्रमुख जड़ी-बूटियाँ:** हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी (जो शरीर की सूजन, थकान और इम्यूनिटी को संतुलित करने में सहायक मानी जाती हैं)

**आहार और सावधानियाँ:** बचाव ही सबसे बड़ा इलाज (Diet & Nutrition Awareness) यहाँ सबसे जरूरी बात आती है—इलाज के साथ शरीर को रोज क्या मिल रहा है? और क्या खाएँ?

\* **क्रूसिफेरस सब्जियाँ:** ब्रोकली, पत्तागोभी

\* **एंटीऑक्सीडेंट फल:** बेरीज, अनार, सिट्रस

\* **साबुत अनाज:** फाइबर युक्त

\* **ग्रीन टी:** पॉलीफेनॉल्स से भरपूर यह सब तभी अरुण करता है जब भोजन नियमित हो, मात्रा सही हो और शरीर उसे पचा सके।

**क्या न करें? (Precautions)**  
\* अत्यधिक चीनी और नमक  
\* प्लास्टिक में गर्म भोजन  
\* तंबाकू और शराब  
ये तीनों इम्यूनिटी सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

**दुर्लभ लेकिन सच**  
\* हाथियों में कैंसर कम क्यों होता है? क्योंकि उनमें p53 जीन ज्यादा होता है — जो कोशिकाओं की सुरक्षा करता है।

\* 12-16 घंटे का नियंत्रित उपवास (Autophagy) शरीर की सफाई प्रक्रिया को सक्रिय करता है।

**निष्कर्ष** (सबसे जरूरी हिस्सा) कैंसर का सामना सिर्फ दवाओं से नहीं होता। उसके लिए शरीर को चाहिए:

\* ताकत  
\* पोषण  
\* संतुलन  
\* निरंतर मार्गदर्शन

1. आधुनिक विज्ञान की सटीकता, और 2. आयुर्वेद की सुरक्षा, और 3. व्यक्तिगत न्यूट्रिशन प्लानिंग — तीनों का तालमेल ही वास्तविक रास्ता है।

अगर आप या आपके परिवार में कोई इस स्थिति से जूझ रहा है... तो सिर्फ जानकारी पढ़कर रुकना काफी नहीं, जरूरी है यह समझना:

\* शरीर को अभी क्या चाहिए  
\* क्या चीज कमजोरी बढ़ा रही है  
\* और कैसे पोषण को इलाज का सहायक बनाया जाए

अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नियमों के भीतर, बिना झूठे वादों के, सही दिशा दिखाए, तो Nutrition & Health Coaching लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।

# रोबोटिक - असिस्टेड रैडिकल प्रोस्टेटेक्टॉमी (RARP) क्या है?

रोबोटिक - असिस्टेड रैडिकल प्रोस्टेटेक्टॉमी (RARP) प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए की जाने वाली एक अत्याधुनिक न्यूनतम इन्वेसिव (Minimally Invasive) शल्य प्रक्रिया है।

इस सर्जरी में पूरा प्रोस्टेट गोल, उसके आसपास के कुछ ऊतक (जैसे सेमिनल वैसिकल्स) और आवश्यकता पड़ने पर पास के लिम्फ नोड्स को भी हटाया जाता है।

यह तकनीक पारंपरिक लैपरोस्कोपिक सर्जरी को उन्नत रोबोटिक तकनीक के साथ जोड़ती है, जिससे सर्जरी अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बनती है। RARP कैसे की जाती है? RARP में सर्जरी प्रत्यक्ष लेंथों से नहीं, बल्कि रोबोटिक प्रणाली की सहायता से की जाती है:

\* घेरे के निचले हिस्से में छोटे-छोटे की-होल (key-hole) घेरे लगाए जाते हैं।

\* इन छिद्रों से रोबोटिक गुजरते, सूक्ष्म सर्जिकल उपकरण और लॉन्ग-हैंड-डिस्क्रीमिनेशन 3D कैमरा जाता जाता है।

\* सर्जन पास ही स्थित एक कंसोल (Console) पर बैठकर इन रोबोटिक गुजरों को नियंत्रित करता है।

\* सर्जन के लेंथों की गतिविधियाँ मशीन द्वारा अत्यंत सूक्ष्म, कंपन-रहित (tremor-free) माइक्रो न्यूट्रिशन में बदल जाती हैं।

इस प्रकार, प्रोस्टेट को पूरी तरह हटाने का लक्ष्य कम से कम शारीरिक क्षति के साथ प्राप्त किया जाता है। RARP क्यों की जाती है? (उपयोगिता) मुख्य

अर्थ: 1. स्थानीयकृत प्रोस्टेट कैंसर का इलाज या नियंत्रण, जब कैंसर केवल प्रोस्टेट तक सीमित हो।

2. कैंसर को शरीर में फैलने से रोकना और रोगी के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना।

अन्य प्रोस्टेट रोगों में इसका सीमित उपयोग संभव है, लेकिन इसका मुख्य अर्थ कैंसर उपचार है। रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी के प्रमुख लाभ पारंपरिक शल्य प्रोस्टेटेक्टॉमी की तुलना में RARP के कई उल्लेखनीय फायदों हैं:

\* न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया

\* कम दर्द

\* छोटे निशान

\* अस्पताल में कम समय

\* जल्दी सामान्य जीवन में वापसी

\* कम रक्तस्राव - घेरे में गैर भरने (Pneumoperitoneum) और सटीक उपकरणों के कारण रक्तस्राव काफी कम होता है।

\* बेहतर दृश्यता और सटीकता 3D लॉन्ग-डिस्क्रीमिनेशन दृश्य से सर्जन को स्पष्ट और बड़ा दृश्य मिलता है। उपकरणों की गति मानव लेंथों से अधिक त्वरित और नियंत्रित होती है।

महत्वपूर्ण नर्वसों की सुरक्षा Nerve-sparing techniques की मदद से:

\* पेशाब पर नियंत्रण (Urinary Continence)

\* यौन क्षमता (Erectile Function) को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकता है।

\* कम शुरुआती जटिलताएँ बड़े अध्ययनों से सिद्ध हुआ



है कि RARP में शुरुआती प्रोस्टेट - ऑपरेटेड जटिलताएँ कम होती हैं।

जोखिम और सावधानियाँ हर बड़ी सर्जरी की तरह RARP में भी कुछ संगठित जोखिम होते हैं:

\* रक्तस्राव या संक्रमण

\* आसपास के अंगों को क्षति

\* अस्थायी या कभी-कभी स्थायी: \* न्यून अंत्रयंत्र (Urinary Incontinence)

\* स्तंभन दोष (Erectile Dysfunction) इसके अलावा:

1. यह प्रक्रिया कई दर्दों में झंझरी है।

2. लंबे समय के कैंसर नियंत्रण परीक्षण सामान्यतः शल्य सर्जरी के समान होते हैं— द्वासरकर अनुभवी

सर्जन द्वारा किए जाते हैं। नवीनतम प्रणाली और अत्याधुनिक विकास रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी निरंतर विकसित हो रही है:

1. शिफा-पोर्ट रोबोटिक सिस्टम

\* पूरी सर्जरी एक ही छोटे घेरे से

\* कम दर्द, कम संक्रमण

\* कुछ मामलों में डे-केयर सर्जरी संभव

2. उन्नत फंक्शनल तकनीकें

\* Retzius-sparing surgery

\* Advanced nerve-sparing approaches

पेशाब नियंत्रण और यौन स्वास्थ्य की तेज़ और बेहतर रिकवरी

भारत में हालिया क्लिनिकल उपयोग से:

\* जल्दी रिकवरी

\* न्यूनतम जटिलताएँ

देखी गई हैं।

3. बढ़ता हुआ उपयोग क्षेत्र अब सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत मामलों में लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर में भी उपयोग वास्तविक जीवन (real-world) परीक्षण प्रशासनिक

4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सर्जिकल एनालिटिक्स

\* रिशत-टाइम सर्जिकल फीडबैक

\* सर्जिकल वीडियो का विश्लेषण

\* नर्सों की सुरक्षा और परीक्षणों की गतिविधायी सर्जन प्रशिक्षण और व्यक्तिगत उपचार योजना में क्रांति

5. सर्टिफिकेटेड और इन्टर-रोबोट तकनीक अलग-अलग रोबोटिक प्रणालियों का संयुक्त उपयोग, अत्यधिक सटीकता और कम घेरे (लॉन्ग-हैंड डिस्क्रीमिनेशन के स्तर पर)

संक्षेप में Robotic-Assisted Radical Prostatectomy (RARP) है:

1. प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक उन्नत न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी

2. उच्च सटीकता, कम शारीरिक क्षति और तेज़ रिकवरी के लिए डिज़ाइन

3. कैंसर नियंत्रण में पारंपरिक सर्जरी के समान प्रभावी

4. निरंतर विकसित होती तकनीकें, निरंतर गतिविधि में परीक्षण और बेहतर लेंथें

5. आने वाले वर्षों में रोबोटिक सर्जरी के कई चिकित्सा क्षेत्रों में मानक उपचार बनने की पूरी संभावना है।

# राउरकेला में स्थायी विज्ञापनों की आड़ में वर्षों से फल-फूल रहा भ्रष्टाचार : महानगर निगम की नई पहल स्वागतयोग्य, पर अधूरी : डॉ. राजकुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, राउरकेला (ओडिशा)

परिवहन विशेष न्यूज

**राउरकेला :** राउरकेला महानगर निगम (RMC) द्वारा शहर सीमा के भीतर अस्थायी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, विज्ञापन वाहनों एवं अस्थायी प्रवेश द्वार (गेट) लगाने हेतु शुल्क निर्धारण एवं पूर्व अनुमति को अनिवार्य किए जाने की निर्णय निरसंदेह एक सकारात्मक कदम है। यह पहल शहर की सुंदरता, स्वच्छता और व्यवस्थित शहरी ढांचे को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।

किंतु इस निर्णय के साथ-साथ यह प्रश्न भी उठाना ही प्रासंगिक है कि आखिर वर्षों तक नगर निगम की आंखों के सामने शहर भर में अनियंत्रित विज्ञापन कैसे लगते रहे? करोड़ों रुपये का राजस्व कहाँ गया? और किन लोगों की मिलीभगत से यह अवैध व्यवस्था फलती-फूलती रही?

**स्थायी विज्ञापन : सौंदर्य बिगाड़ने के साथ राजस्व की खुली लूट**

राउरकेला जैसे औद्योगिक एवं शैक्षणिक शहर में पिछले एक दशक से अस्थायी विज्ञापनों की बाढ़ देखी जा रही है। राजनीतिक दलों के पोस्टर, निजी कंपनियों के बैनर, कोचिंग संस्थानों के होर्डिंग, धार्मिक आयोजनों के प्रवेश द्वार, और प्रचार वाहनों का उपयोग बिना किसी स्पष्ट अनुमति प्रक्रिया के खुलेआम होता रहा है।

नगर के मुख्य चौराहों, सड़कों के डिवाइडरों, सरकारी भवनों की दीवारों, बिजली के खंभों और यहां तक कि स्कूलों एवं अस्पतालों के आसपास भी अवैध

विज्ञापन लगाए जाते रहे हैं। इससे न केवल यातायात बाधित हुआ, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ी और शहर की छवि एक अव्यवस्थित कस्बे जैसी बनती चली गई।

**नियमों का कागजों तक सीमित रह जाना**

नगर निगम अधिनियम और विज्ञापन उपविधियों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर विज्ञापन लगाने से पूर्व अनुमति लेना और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। इसके बावजूद वर्षों तक इन नियमों का पालन नहीं हुआ।

**प्रश्न यह है कि—** क्या महानगर निगम को इन अवैध गतिविधियों की जानकारी नहीं थी?

**क्या निगरानी तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय था?** या फिर यह सब कुछ एक सुनिश्चित मिलीभगत का परिणाम था?

जमीनी हकीकत यही दर्शाती है कि यह तीसरा कारण अधिक प्रबल है।

\* विज्ञापन ठेका : भ्रष्टाचार की जड़ - राउरकेला महानगर निगम में विज्ञापन प्रबंधन का कार्य सामान्यतः ठेका प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है। नियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में या निर्धारित अवधि के बाद पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

**परंतु वास्तविकता यह है कि—** कई वर्षों से नए टेंडर जारी नहीं किए गए, पुराने ठेकेदारों को ही नगज्य शुल्क व

अनौपचारिक रूप से काम करने दिया गया, और बिना किसी प्रतिस्पर्धा के करोड़ों रुपये के सौभाग्य प्राप्त करने में नगर निगम को विफल किया गया।

विश्वसनीय सूत्रों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, यदि विज्ञापन शुल्क का विधिवत संग्रह किया जाता, तो नगर निगम को प्रतिवर्ष कई करोड़ों रुपये तक की आय हो सकती थी। यह शहर सड़क मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइटिंग और गरीब बस्तियों के विकास में लगाई जा सकती थी।

**"बंदरबांट" का खुला खेल**

वर्षों से देखने में आ रहा है कि कुछ चुनिंदा एजेंसियों और अधिकारियों के बीच एक अशोषित समझौता बना हुआ था।

**विज्ञापन लगाने की छूट दी जाती रही,** मामूली राशि निजी तौर पर वसूली जाती रही, और सरकारी रिकॉर्ड में वास्तविक आंकड़े कभी दर्ज ही नहीं हुए।

यह व्यवस्था पूरी तरह "बंदरबांट" पर आधारित थी, जिसमें नगर निगम का राजस्व कुछ व्यक्तियों की जेब में जाता रहा।

**आम जनता को हुआ सीधा नुकसान** इस भ्रष्ट व्यवस्था का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ा।

टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, बरसात में जलजमाव की समस्या बढ़ती रही, कचरा प्रबंधन बहाल रहा,

और बुनियादी नागरिक सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष करते रहे।

जब महानगर निगम के पास संसाधन होते हुए भी उनका उपयोग नहीं होता, तो यह सीधा-सीधा प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार का प्रमाण है।

नई शुल्क व्यवस्था : स्वागत योग्य, पर पर्याप्त नहीं RMC द्वारा अब अस्थायी विज्ञापनों के लिए शुल्क तय करना एक सराहनीय कदम है। यह—

दृश्य प्रदूष



## अब हर सोमवार और शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में होगी जन-सुनवाई

परिवहन विशेष न्यूज

मुख्य सचिव, बिहार सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर नई कार्य-योजना की जानकारी दी गई।

19 जनवरी 2026 से जिले के पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी कार्यालयों में सप्ताह के दो दिन विशेष रूप से जन-सुनवाई के लिए कार्य होगा।

**नई व्यवस्था की मुख्य बातें:**

प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को सभी अधिकारी अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

यह व्यवस्था ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों पर लागू होगी। आम नागरिक इन दो दिनों में सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे।

## विधायक डॉ अजय गुप्ता की पत्नी स्व. रेणु गुप्ता की आत्मिक शांति के लिए हुई श्रद्धांजलि सभा: अलग-अलग वर्ग के लोगों ने पारिवारिक सदस्यों संग जताया शोक

अमृतसर, 16 जनवरी (साहिल बेरी)

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र अमृतसर से विधायक डॉ अजय गुप्ता की धर्मपत्नी रेणु गुप्ता का 13 जनवरी की रात को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई थी। स्व. रेणु गुप्ता की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा आज शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक मालिवु गार्डन, वेरका-मजीठा बायपास रोड अमृतसर में संपन्न हुई। श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में लोगों ने पारिवारिक सदस्यों के साथ शोक व्यक्त किया।

श्रद्धांजलि सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा भेजा गया शोक संदेश पढ़ा गया। आज प्रार्थना सभा में आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज व दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम



से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित दिनों पर अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। अधिकारी आगंतुकों से सम्मानपूर्वक मिलें और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ

सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहता है, तो उनके द्वारा अधिकृत अन्य पदाधिकारी जनता की समस्याओं को सुनेंगे। अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों को भी समय बांटकर अपने सभी संबंधित कार्यालयों में

उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है।

जन-सुनवाई के दौरान आने वाली जनता की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा गया है। सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करें।

स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करें। एक 'शिकायत पंजी' संधारित करें ताकि शिकायतों के निवारण की मॉनिटरिंग की जा सके।

इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शिता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। वे हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालयों में होने वाली जन-सुनवाई की फोटोग्राफी और रिपोर्ट संकलित कर सीधे जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे।



मनीष सिंसोदिया, आम आदमी पार्टी पंजाब के कार्यकारी प्रधान एवं विधायक शैरी कलसी, विधायक डॉ इंद्रबीर सिंह निज्जर, विधायक जसबीर सिंह संधू, विधायक जीवन्तजोत कौर, विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, मेयर

जतिंदर सिंह मोती भाटिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ राजकुमार वेरका, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमित जोशी, पूर्व पूर्व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी डॉ नवजोत कौर सिद्धू, पूर्व विधायक सुनील दत्ता, पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल, डिप्टी मेयर अनीता रानी के पुत्र तरुणवीर कैडी, पार्षद

## बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के 22 वर्ष पूरे

### 'नई श्रम संहितायें: मजदूर वर्ग पर हमला' विषयक विचार गोष्ठी

मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं के खिलाफ संघर्ष का ऐलान

शुभेंद्र सारस्वत, सारथी)

केंद्र की मोदी सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं। देशभर की दस बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने इनका खूला विरोध किया है। इसी क्रम में बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन द्वारा 18 जनवरी को रोटी भवन में सुबह 11 बजे से विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता बी टी यू एफ के अध्यक्ष मुकेश सक्सेना ने की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिश्रील सांस्कृतिक मंच द्वारा प्रस्तुत जोशीले गीतों से हुई।

गोष्ठी की शुरुआत में बी टी यू एफ के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के 22 साल पूरे होने पर इसके इतिहास और शहर में की गई गतिविधियों, विरोध प्रदर्शनों और सामाजिक सरोकार के विषय में बताया। उन्होंने कहा फेडरेशन ने अपनी स्थापना के बाद से ही मजदूरों-कर्मचारियों के मुद्दों पर बरेली शहर में व्यापक एकता बनाने की लगातार कोशिश की है। आज जब श्रम संहिताओं को लागू कर मजदूरों/कर्मचारियों के हितों पर



हमला किया जा रहा है तब हमें और व्यापक एकजुटता कायम कर संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा।

बी टी यू एफ के उपाध्यक्ष ध्यान चन्द्र मौर्य ने मजदूर आंदोलनों और श्रम कानूनों के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मजदूर वर्ग राजनीतिक तौर पर सजग था और संघर्ष कर रहा था तो उसके हित में कई कानून बने। यहाँ तक कि अंग्रेजों के दौर में भी उन्हें मजदूर हितों के कानून बनाने को मजबूर किया गया। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार मजदूर हित में बने श्रम कानूनों को खत्म कर, नई श्रम संहिताओं को

लागू कर, मजदूरों को फिर से गुलामी के दौर में धकेलना चाहती है। हमें मजदूर वर्ग की व्यापक एकता कायम कर इसका मुकाबला करना होगा। मुख्य वक्ता आल इंडिया इश्योरेंस इम्प्लाइड एम्प्लॉयमेंट के पूर्व अध्यक्ष अमान उल्ला खान, जो बैंगलोर से पधारें थे, ने अपने लंबे संबोधन में चार लेबर कोड्स की कड़ी खिलाफती की। उन्होंने इनके लागू होने से संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को होने वाली दुखवारियों को समझाया। उन्होंने कहा इन संहिताओं में मजदूरों के लिए यूनियन बनाना और हड़ताल करना

लगभग असंभव बना दिया गया है। काम के घंटे बढ़ाने और न्यूनतम वेतन को गिराने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में पूरे देश में इन मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं का मुखर विरोध होना ही है। इसके लिए हमें इस विषय की जानकारी होना जरूरी है। जिस तरह किसानों ने लंबी लड़ाई के बाद काले कृषि कानूनों को वापस कराया। उसी तरह देश के मजदूरों-कर्मचारियों को भी लंबी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। इसी कड़ी में देश के 50 करोड़ मेहनतकश 12 फरवरी को सड़क पर उतर कर इन चार लेबर कोड्स का

कड़ा प्रतिरोध करेंगे। उन्होंने कहा रास्ता हमें ही निकालना होगा, उन्होंने कहा सरकार पूंजिपतियों पर वेलथ टैक्स और इन्हें टैक्स लगाना चाहिए।

गोष्ठी में सर्व श्री डॉ अंचल अहरी, गीता शांत, जतिंदर मिश्रा, नवींद्र कुमार, सिलेन अहमद, रजनीश तिवारी, राजेंद्र सिंह, हरि शंकर, के पी सिंह, अरविंद देव सेवक, कैलाश, टी डी भास्कर, मिशन पाल सिंह आदि ने भी विचार रखे। गोष्ठी का संचालन बी टी यू एफ के उप महामंत्री ललित चौधरी ने किया।

गोष्ठी में देव सिंह, डॉ. मुनीश गंगवार, चरण सिंह यादव, मोहित देवल, हिमांशु सिंह, पुष्पा गंगवार, दिशा, निशा, रुचिका वर्मा, मो. फैसल, एड. यशपाल सिंह, एड. ऋषिपाल सिंह, सुरेंद्र प्रजापति, डॉ. रजनीश गंगवार, जगपाल भाटी, हरचरण लाल गंगवार, रवि कुमार, संदीप सिंह, मनोज गुप्ता, भगवान दास, उपेश मौर्य, जसुना देवी, रीना कोरी, अर्चना कुमारी, राशिदा सूरी, सौरभ शर्मा, सर्वेश मौर्य, राहुल गौड़, राकेश कर्नौलिया, दीपक मेहरा, हरगोविंद मौर्य, सुनील गौतम सहित कई अन्य साथी मौजूद रहे।

## सोशल मीडिया पर उठी पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजे जाने की मांग

राज शेखर | नई दिल्ली |

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज होती दिखाई दे रही है। ट्विटर (एक्स), फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस समर्थक, कार्यकर्ता और कई स्वतंत्र सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणीकार लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि पार्टी को इस बार पवन खेड़ा जैसे मुखर और वैचारिक नेता को राज्यसभा भेजना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, हाल के महीनों में सामने आए कई अनौपचारिक सर्वे और आंतरिक आकलनों में पवन खेड़ा का नाम संभावित राज्यसभा उम्मीदवारों में सबसे आगे बताया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो संसद के उच्च सदन में न केवल सरकार से तो खेड़ा के मुद्दों को मजबूती से उठा सकें।

पवन खेड़ा बीते एक दशक से कांग्रेस पार्टी के वैचारिक मोर्चे पर एक सशक्त आवाज के रूप में उभरे हैं। पार्टी के डिबेट्स में उनकी स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित शैली, सरकार की नीतियों पर बेबाक आलोचना और विषय की भूमिका को मजबूती से रखने का अंदाज उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान देता है। पार्टी के भीतर भी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी संगठन की लाइन को मजबूती से



सामने रखते हैं।

सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम में यह तर्क प्रमुखता से उभरकर सामने आ रहा है कि पवन खेड़ा ने केवल स्टूडियो डिबेट्स तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सड़क से लेकर संसद के बाहर तक पार्टी की लड़ाई को आवाज दी। चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हो, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का सवाल या फिर आम जनता से जुड़े आर्थिक और सामाजिक विषय—पवन खेड़ा लगातार मुखर रहे हैं।

इस चर्चा को और गहराई तक मिली जब समर्थकों ने पवन खेड़ा के उस पुराने बयान को फिर से साक्षात्कार शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "तपस्या में कहीं न कहीं कमी रह गई थी।" उस वक्त उनके इस कथन को राजनीतिक विनम्रता और आत्ममंथन के रूप में देखा गया था।

आज उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक तपस्या को और अधिक मजबूत किया है और अब वह अनुभव, संघर्ष और वैचारिक परिपक्वता के उस मुकाम पर हैं, जहाँ उन्हें राज्यसभा जैसे मंच पर देश की आवाज बनना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं का यह भी

कहना है कि राज्यसभा में पवन खेड़ा की मौजूदगी कांग्रेस को बौद्धिक और वैचारिक मजबूती देगी। उनका मानना है कि जिस तरह से सत्तारूढ़ दल संसद के भीतर आक्रामक रणनीति अपनाता है, उसके जवाब में कांग्रेस को भी ऐसे वक्ताओं की जरूरत है जो तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर प्रभावी हस्तक्षेप कर सकें।

हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा के समर्थन में लगातार आवाज बुलंद हो रही है, उससे यह साफ है कि यह केवल डिजिटल शोर नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर और बाहर मौजूद एक व्यापक भावना का प्रतिबिंब है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर होने वाले फैसलों में इस जनभावना का असर जरूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजे जाने की मांग ने राजनीतिक गतिवारों में नई बहस छेड़ दी है और यह मुद्दा आने वाले समय में और अधिक सुर्खियों में रहने वाला है।

## 'आप' सरकार के प्रयासों से गांव गुमटाला में 70 वर्षों बाद पहली बार पहुंचेगा सरकारी पीने का पानी: जसबीर सिंह संधू



अमृतसर (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी के अमृतसर पश्चिमी हलके से विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू और नगर निगम अमृतसर के मेयर जतिंदर सिंह भाटिया द्वारा वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आने वाले गांव गुमटाला में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वार्ड काउंसलर अमरजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

इस मौके पर विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू ने कहा कि भारत को आजाद हुए 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन गांव गुमटाला जैसे इलाके अब तक सरकारी पीने के पानी की सुविधा से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी इस बुनियादी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 'आप' सरकार ने सत्ता

में आते ही जनता की मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि 70 वर्षों के बाद पहली बार गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है और जल्द ही इन्हें ट्यूबवेल से जोड़कर सरकारी पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।

मेयर जतिंदर सिंह भाटिया ने कहा कि गांव गुमटाला के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी, जिसे अब 'आप' सरकार ने पूरा कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सफ और शुद्ध पीने का पानी हर नागरिक का अधिकार है और नगर निगम इस प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। ट्यूबवेल से जोड़ने के बाद गांव के हर घर तक नियमित पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। अंत में विधायक डॉ. जसबीर सिंह

संधू ने कहा कि 'आप' सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को बुनियादी सुविधाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अमृतसर पश्चिमी हलके के हर वार्ड और गांव में विकास कार्य तेजी से करवाए जा रहे हैं और आने वाले समय में पानी, सड़क, सोवरेज और सफाई जैसे मुद्दों को और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि 'आप' सरकार जनता से किया गया हर वादा पूरी ईमानदारी से पूरा करेगी।

इस अवसर पर वरिंदरजीत सिंह बेदी पट्टी वाले पश्चिमी हलके के संगठन इंचार्ज हरप्रीत सिंह बेदी, बर्लाक प्रधान जनक चर जोशी, तरसेम कल्याण, लाड़ी सहोता, पीए माधव शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

## बृज यातायात एवं पर्यावरण समिति कड़ाके की ठंड में बांट रही कंबल

पिछले 15 दिनों से समिति लोगों को कड़ाके की ठंड में कंबल बांट रही है संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित

परिवहन विशेष न्यूज

बृज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति रजि उत्तर प्रदेश की कंबल वितरित सेवा

पिछले 1 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक लगातार गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किये जा रहे हैं। संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने बताया है कि हमारी संस्था इस कड़ाके की ठंड में लगातार कंबलों का वितरण लोगों को अलग-अलग स्थान पर

किया जा रहा है। हमारी संस्था का स्लोगन है जिंदगी अनमोल है इससे बचना हम सबकी जिम्मेदारी इसी के अंतर्गत पूरे साल भर अलग-अलग तरह के कार्यक्रम लोगों की जरूरत के हिसाब से किए जाते हैं। महिला महिला प्रदेश अध्यक्ष श्वेता शर्मा ने कहा हम लोग इस कड़ाके

की ठंड में लोगों को लगातार अपनी संस्था के माध्यम से मदद कर रही है इसमें महिला टीम भी अपनी सहभागिता निभा रही है। आज दर रात हमारी टीम ठंड से बचने के लिए जगह-जगह पर जाकर जरूरतमंद लोगों को कंबल दिए हैं यह हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा।

## अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई — नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 03 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और अत्याधुनिक हथियार बरामद

अमृतसर, 16 जनवरी (साहिल बेरी)

माननीय मुख्यमंत्री पंजाब एवं माननीय डीजीपी पंजाब द्वारा नशा माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए जारी सख्त दिशा-निर्देशों के तहत, श्री संदीप गौयल, आईपीएस, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल और पुलिस, बॉर्डर रेंज तथा श्री सुहेल मीर, आईपीएस, सीनियर सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस, अमृतसर ग्रामीण के नेतृत्व में अमृतसर ग्रामीण पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी, निर्णायक और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है।

**गिरफ्तार आरोपी:**

अजुल अरोड़ा पुत्र अनिल अरोड़ा, निवासी बाग रामा आनंद, गली नंबर 3, स्टावर बुटीक, धी मंडी, अमृतसर।

दिलप्रीत कौर पत्नी सुखजोत सिंह, निवासी बाबा दर्शन सिंह एवेन्यू।

प्रथम शर्मा पुत्र राजीव कुमार, निवासी गांव महल।

स्पेशल सेल अमृतसर ग्रामीण की टीम ने सबसे पहले आरोपी अजुल अरोड़ा को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना लोपोके में मुकदमा नंबर 08 दिनांक 06.01.2026 धारा 21(सी), 25, 29, 61, 85 एनडीपीएस एक्ट तथा 25(8), 54, 59 आर्मास एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से:

04 किलो 863 ग्राम हेरोइन  
02 पिस्टल (9 एएमएम)  
10 जिंदा कारतूस  
बरामद किए गए।

अजुल अरोड़ा से गहन पूछताछ के दौरान उसके अन्य साथियों के बारे में अहम जानकारियां सामने आईं, जिसके आधार पर पुलिस ने दिलप्रीत कौर और प्रथम शर्मा को भी गिरफ्तार किया।



**इनकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस ने:**

02 PX5 पिस्टल  
01 पंप एक्शन राइफल (12 बोर)

45 जिंदा कारतूस (12 बोर)

01 संप्रिंगफोल्ड राइफल  
25 जिंदा कारतूस  
04 जिंदा कारतूस (.30 बोर)

बरामद किए।

तपशील के दौरान नामजद आरोपी: अभिराज सिंह उर्फ अब्बी महल पुत्र सुखजोत सिंह, निवासी बाबा दर्शन सिंह एवेन्यू, घनपूर, काले, छेहटा।

नंदनी शर्मा पुत्री राजीव कुमार, निवासी जट्टों के गुरुद्वारे के पास, गांव महल।

सतबीर सिंह उर्फ सत्ता नौशहरा (फरार)

**कुल बरामदगी:**  
हेरोइन: 04 किलो 863 ग्राम  
पिस्टल: 04 (02 पिस्टल 9 एएमएम और 02 PX5 पिस्टल)

राइफल: 02 (01 पंप एक्शन राइफल 12 बोर, 01 संप्रिंगफोल्ड राइफल)  
जिंदा कारतूस: 84  
10 (9 एएमएम)  
45 (12 बोर)  
25 (संप्रिंगफोल्ड)

04 (.30 बोर)

वाहन: 02 (एक आई-20 और एक होंडा सिटी)

**अपराधिकारिकों:**  
सतबीर सिंह उर्फ सत्ता नौशहरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज हैं।

अभिराज सिंह उर्फ अब्बी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज हैं।

प्रथम शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमा: मुकदमा नंबर 166/25, धारा 21-बी/27-ए/29/62/85 एनडीपीएस एक्ट, थाना छेहटा। नामजद और अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की गहराई से जांच जारी है। जांच के दौरान जो भी व्यक्ति नशा तस्करी से जुड़ा पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।